UPSC MAINS · ANSWER PRACTICE

Indian Economy · GS - III

भारत में दवाओं के मूल्य

विनियमन की चुनौतियों पर चर्चा
कीजिए। उपभोक्ता हितों की

रक्षा के लिए आवश्यक उपाय

सुझाइए।

EXAM YEAR

DAILY PRACTICE 17/10/2026

PAPER

GS - III

SUBJECT

Indian Economy

MARKS

10

WORD LIMIT

~150 words

Answer Hint

NPPA, DPCO, आवश्यक दवाएँ , MRP, भ्रामक छूट, उपभोक्ता संरक्षण ,
पारदर्शिता , नियामक निगरानी।

Model Answer

भूमिका :

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक पहुँच सार्वजनिक स्वास्थ्य का
महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) और
वास्तविक कीमत के बीच बड़ा अंतर उपभोक्ता संरक्षण तथा मूल्य
विनियमन से जुड़े प्रश्न उठाता है।

मुख्य भाग:

मूल्य पारदर्शिता : MRP अधिक रखकर भारी छूट दिखाने से उपभोक्ताओं
को दवा की वास्तविक कीमत का आकलन करने में कठिनाई हो सकती है।

1. विनियमन की सीमाएँ : सभी दवाएँ सरकारी मूल्य नियंत्रण के दायरे
में नहीं आतीं।

www.becomeias.com YouTube: becomIAS | Instagram: howtobecomeias

2. आर्थिक बोझ: महँगी दवाएँ मरीजों और
विशेषकर गरीब परिवारों के स्वास्थ्य
व्यय को बढ़ाती हैं।
3. जागरूकता की कमी: उपभोक्ताओं को
जेनेरिक दवाओं , निर्धारित कीमतों और
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की
पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

सुधार के उपाय :

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
(NPPA) द्वारा प्रभावी निगरानी , मूल्य
निर्धारण में पारदर्शिता , भ्रामक छूट पर
उचित कार्रवाई , नियमित बाजार निरीक्षण और
जन -जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष : मजबूत मूल्य विनियमन और
जवाबदेही से दवाओं को अधिक किफायती बनाया
जा सकता है तथा उपभोक्ताओं का विश्वास
बढ़ाया जा सकता है।

www.becomeias.com YouTube: becomIAS | Instagram: howtobecomeias